

प्रेषक

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
श्रीनगर- गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं नकलीकी शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 01 जुलाई, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति को बजट अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(I)/2017 दिनांक 30.06.2017, भारत सरकार के पत्र संख्या-F.No.-B-12012/19/2017SNP दिनांक 28.04.2017 एवं परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति, देहरादून के पत्र संख्या 273/यूकेएसडीएम/बजट/2017-18 दिनांक 01.07.2017 (छायाप्रति संलग्नक) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु. 25.00 करोड में से रु. 20,32,43,040 (रु. बीस करोड बत्तीस लाख तैतालीस हजार चालीस मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का आहरण कर मिशन निदेशक, उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति, देहरादून को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित किया जायेगा। मिशन निदेशक द्वारा उपरोक्त धनराशि को विभिन्न मदों में व्यय करने का नियमानुसार प्रस्ताव The Board of Governors से पारित कराकर अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
2. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.06.2017 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर अधिष्ठान संबंधी मदों की आय-व्ययक के अन्तर्गत स्वीकृत बजट प्राविधान की धनराशि संबंधित प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा आहरण-वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबंध के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट को प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि की कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।
4. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्थोरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों को अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 7. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन समक्ष अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
 8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक नहीं हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
 9. लाभार्थी के रूप में चयन बजट प्राविधान के अनुसार किया जाएगा। लाभार्थियों की आधारयुक्त बायोमैट्रिक्स उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
 10. राज्य कौशल विकास मिशन को वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रशिक्षण कार्यक्रम को तत्काल प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
 11. भारत सरकार के पत्र संख्या-F.No.-B-12012/19/2017SNP दिनांक 28.04.2017 में उल्लिखित शर्तों तथा शासनादेश के साथ Description of the project Submitted by Uttarakhand skill Development Mission (UKSDM) Government of Uttarakhand में उल्लिखित लक्ष्यों तथा दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 12. PMKVY परियोजना के क्रियान्वयन में राज्य एवं केन्द्र स्तर पर निर्गत सभी गाइडलाइन्स का अक्षरशः पालन किया जाएगा, खासकर परियोजना के प्रचार-प्रसार हेतु।
 13. PMKVY परियोजना हेतु निर्गत सभी गाइडलाइन्स के निर्देशों का पालन किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की अनदेखी या उल्लंघन नहीं किया जाएगा, जिसके कारण भविष्य में राज्य को धनराशि निर्गत करने में कठिनाई उत्पन्न हो।
 14. स्वीकृत धनराशि भारत सरकार के पत्र संख्या-F.No.-B-12012/19/2017SNP दिनांक 28.04.2017 तथा संलग्नक में दिये गये निर्देशों के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक के 'अनुदान संख्या 11' के लेखाशीर्षक "2203-तकनीकी शिक्षा-001-निदेशन तथा प्रशासन-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0102-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में WWW.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/आलॉटमेंट आई.डी. संलग्न-1 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।
- संलग्न-उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

(ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव,

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति, आई0टी0आई0 देहरादून।
7. बजट, राजकोषिय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी.एस. बिष्ट)
उप सचिव